दीर्घकालिक दृष्टिकोण

लेखक - आशिमा गोयल (प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

6 जुलाई, 2019

"बजट एक नए भारत के दीर्घकालिक निर्माण का हिस्सा है और यह पिछले कार्यकाल के दृष्टिकोण को दर्शाता है।"

17वीं लोकसभा में नई सरकार का पहला बजट शक्तिशाली दृष्टि से अंतिम अवधि को निर्देशित करने की सलाह देता है, जिसमें राष्ट्र निर्माण, राजकोषीय समेकन, अनुशासन और प्रक्रिया में सुधार के लिए निरंतरता, व्यक्तिगत सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए किसानों की आय दोगुनी करने के साधन के रूप में आय हस्तांतरण नहीं, बल्कि मूल्य संवध ्रन और रूपांतरण पर ध्यान दिया गया है।

लेकिन एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण को चुनने में, शायद ही, वर्तमान विकास मंदी और बजट इसे कम करने में कैसे योगदान दे सकता है, पर चर्चा होती है। यह अफसोस की बात है क्योंकि यह सरकार के प्रमुख वृहद् आर्थिक नीति विवरण से अपेक्षित है। बाजार, विकास को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार से बड़े स्तर पर खर्च को बढ़ावा देने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन बजट के कई पहलू हैं जो विकास को पुनर्जीवित करने में योगदान करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं लाया गया है। बजट को नए भारत के दीर्घकालिक निर्माण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

मैक्रो इकोनॉमिक प्रोत्साहन का मानक विचार करों को बढ़ाए बिना सरकारी खर्च में बड़ी वृद्धि की घोषणा करता है। इससे घाटा बढ़ता है। बजट के संदर्भ में सक्रिय रूप से बहस हो रही है कि मंदी को देखते हुए घाटे में वृद्धि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्वीकार्य है, लेकिन सरकार लंबी अवधि के व्यापक आर्थिक ढांचे और घाटे में कमी के मार्ग के लिए प्रतिबद्ध है। एक विचलन इसकी विश्वसनीयता को चोट पहुंचाएगा। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के अन्य तरीके भी हैं। पिछली सरकारों द्वारा खर्च और अधिक प्रोत्साहन के कारण भारत को व्यापक आर्थिक नाजुकता और उच्च मुद्रास्फीति से बचने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है।

मैक्रो इकोनॉमिक उत्तेजना

बजट इस सरकार के बुनियादी ढांचे में वितरण की तेज गति, जैसे-सड़क निर्माण या कम आय वाले आवास के निर्माण के कई उदाहरण देता है। चूंकि पिछली सरकार ही वापस आई है, इसलिए यह तैयार परियोजनाओं पर किये जाने वाले व्यय का भार उठाने में सक्षम होगी। आय के निर्माण के अलावा यह सीमेंट और इस्पात उद्योगों की मांग को बढ़ाता है। हालांकि, अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का अनुपात 3.4 से घटकर 3.3 हो गया है, इसलिए निजीकरण द्वारा संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा जुटाया जाना शेष है। चूंकि यह कराधान के समान निजी मांग को कम नहीं करता है, इसलिए एक बड़ा शुद्ध व्यय प्रोत्साहन है जो मांग और विकास का समर्थन करता है। पूर्ण योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें स्वच्छ भारत के कुछ धन को पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति करने के लिए और ठोस कृषि प्रबंधन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फिर से आवंटित किया जा रहा है।

तेजी से निजीकरण के साथ-साथ अन्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण, जैसे कि ब्राउन फील्ड परियोजनाएं और सरकारी भूमि बैंक निजी गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगे। परिसंपत्ति परिमार्जन के बाद आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए उपायों की एक श्रृंखला के साथ ऋण वृद्धि में मदद् मिलेगी।

जलवायु का निराशावाद और भय, क्रेडिट विकास की गिरावट के लिए जिम्मेदार था, जो निजी निवेश और खपत में मंदी का कारण बना। सरकार की भूमिका आत्मविश्वास बढ़ाने की है। 2017 के अंत में निजी निवेश परियोजनाएं शुरू हो गई थीं, लेकिन जैसे कि कुछ क्षेत्र क्षमता की कमी के शिकार थे, एनबीएफसी क्रेडिट मंदी और चुनाव संबंधी राजनीतिक अनिश्चितता के कारण कमजोर पड़ गयीं। इसे फिर से पुनर्जीवित करना

GS World Committed To Excellence

चाहिए, खासकर वर्तमान संदर्भ को देखते हुए जहाँ ब्याज दरों में कमी होना जारी है। बजट के बाद सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) की दरें गिर गई हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड और एनबीएफसी फंड में भी कमी आनी चाहिए। कई NBFC के पास व्यवहार्य व्यावसायिक मॉडल हैं। जैसे-जैसे लागत में कमी आएगी और गतिविधि में सुधार होगा, क्रेडिट रिस्क का भय कम होगा। मृतप्राय अचल संपत्ति बाजार, जो परिसंपत्ति मूल्य के विनाश के लिए जिम्मेदार है, उसे कर छूट और कम ब्याज दरों से प्रोत्साहन मिलेगा।

उद्योगों को कई अन्य तरीकों से मदद् का वादा किया गया है, जिसमें भूमि की उपलब्धता, श्रम कानून सरलीकरण, कानूनी लागत में कमी, देरी और कर उत्पीड़न की समस्या से छुटकारा शामिल हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी और उद्यमिता के लिए समर्थन पर ध्यान केंद्रित करने से उद्योग के लिए कई अवसर पैदा होंगे। निजी फर्म आम तौर पर सार्वजनिक सेवाओं के अंतिम वितरण में बेहतर सहयोग करती हैं। भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने में कॉरपोरेट करों में कटौती, टैरिफों का सामान्यीकरण बेहतर कदम साबित हो सकता है। चीन से दोबारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में इस तरह की पहल कारगर साबित हो सकती है।

पिछली सरकार की ताकत प्रक्रिया में सुधार थी, जो इस बजट में भी जारी है। बिना मानव इंटरफेस के फेसलेस ई-मूल्यांकन की एक नई पहल और यादृच्छिक तरीके से सौंपे गए मामलों से करदाता उत्पीड़न में कमी आएगी। एकीकृत जानकारी का उपयोग ऑटो फॉर टैक्स फॉर्म भरने के लिए किया जाएगा, जिससे अनुपालन आसान हो जाएगा क्योंकि इससे कर चोरी अधिक कठिन हो जाएगी। वस्तु और सेवा कर एवं अन्य करों में अधिक सरलीकरण है एवं कर आधार को बढ़ाने के लिए सूचना का अधिक गहनता से उपयोग किया जाएगा।

प्रक्रियाओं में सुधार बजट में किये गये वादों के बेहतर वितरण और राजकोषीय समेकन की गुणवत्ता को दर्शाता है। राजस्व घाटे के साथ-साथ राजकोषीय घाटे में भी गिरावट आई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) के बाजार उधार से पूंजीगत व्यय का समर्थन किया गया था।

शासन में सुधार के बिना प्रौद्योगिकी पर जोर देने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन दोनों पर पूरक कार्रवाई का सबूत है। उदाहरण के लिए, छोटे व्यवसायों के लिए एक प्रमुख बाधा सरकार द्वारा समय पर भुगतान की अनुपस्थिति है। समय कम करने और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए एक भुगतान मंच की घोषणा की गई है। साथ ही पानी से संबंधित मंत्रालयों को मिला दिया गया है।

एक प्रमुख बाधा जिसका सामना भारत को करना पड़ रहा है, वह बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक धन का अभाव है। सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए खुदरा निवेशकों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक डिपॉजिटरी के बीच अंतर-संचालन द्वारा समर्थन किया जाना है।

चूंकि ये सुधार आपूर्ति-पक्ष में सुधार करते हैं, इसलिए लागत और समय की देरी व्यवसाय के साथ-साथ औसत नागरिक के लिए भी कम हो जाती है।

दीर्घकालिक ढांचा

जैसा कि ऊपर तर्क दिया गया है कि घाटे को बढ़ाए बिना कुछ उत्तेजना संभव है। विकास में व्याप्त मंदी का मुकाबला करने के लिए एक नीति की आवश्यकता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन समायोजन मार्ग व्यय की गुणवत्ता की रक्षा के लिए प्रोत्साहन के साथ एक चक्रीय रूप से समायोजित राजकोषीय घाटे के संदर्भ में होना चाहिए। राजस्व घाटे के लिए एक लक्ष्य भी आवश्यक है। 15वें वित्त आयोग को इस पर विचार करना चाहिए।

ऋण और ब्याज भुगतान के स्तर को कम करना वांछनीय है, क्योंकि यह उत्पादक व्यय के लिए बहुत अधिक सरकारी धन जारी करेगा। विकास से कर राजस्व में वृद्धि होती है और जीडीपी में वृद्धि से घाटे को कम करने वाले क्षेत्र में वृद्धि होती है। इसलिए विकास को बनाए रखना ऋण और घाटे के अनुपात को कम करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है।

CS World
Committed To Excellence

बजट - 2019

परिचय

- हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में मोदी सरकार कि 2.0 का पहला बजट पेश किया।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत 'मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक' के नारे के साथ किया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले पाँच साल में हमने देश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने का काम किया है।
- हमारा लक्ष्य लोगों के घरों में शौचालय पहुँचाना, घरों में बिजली पहुँचाना था।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी को बढ़ावा देने और ऋण में सुधार के लिए 70,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाने हैं।
- भारतमाला, सागरमाला और उड़ान (UDAN) यूडीएएन जैसी योजनाएं हमारे परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करते हुए ग्रामीण और शहरी विभाजन को कम कर रही हैं।
- भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वर्ष में ही 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह अब दुनिया में छठा सबसे बड़ा है। 5 साल पहले यह 11 वें स्थान पर था।

कृषि क्षेत्र के लिए

- गाँव, गरीब, किसान पर खास फोकस होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2022 तक हर गाँव में बिजली होगी। साथ ही 1.95 करोड़ नए घर बनाने की योजना है।
- साल 2024 तक गाँव के हर घर तक जल (पानी) पहुँचाया जाएगा। इसमें हर घर में टंकी से पानी पहुँचाया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत साल 2019-20 से साल 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे।
- इनमें रसोई गैस, बिजली और शौचालयों जैसी सुविधा होगी। पहले आवासों को बनाने में जहाँ 314 दिन लग रहे थे, अब 114 दिन लगते हैं।
- 5.6 लाख गाँव अबतक खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। 02 अक्टूबर 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा।
- साल 2022 तक 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।
- मछुआरों की आजीविका को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्यिकी ढाँचे की स्थापना होगी।
- वित्त मंत्री ने बजट भाषण में 'जलजीवन मिशन' के तहत साल 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा।
- गरीबों के लिए साल 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सभी को घर उपलब्ध कराने की बात कही।
- सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल शिक्षा (Digital Education) देने का लक्ष्य रखा है।

रेलवे के लिए

- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-20 के बजट में 300 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।
- इस वर्ष 657 किलोमीटर नए मेट्रो रेल नेटवर्क पर संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
- भारतीय रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट में पीपीपी मॉडल के जरिए निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
- उन्होंने बजट में रेलवे ट्रैक के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी प्रदान कर दी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल से रेलवे के विकास में तेजी आएगी।
- स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए रेलवे ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। फ्रांस के साथ हुए इस समझौते के तहत ढांचागत विकास पर सरकार सात लाख यूरो खर्च करेगी।
- केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि रेलवे नेटवर्क का कंजेशन खत्म करने के लिए जलमार्ग भी तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है।
- वित्तमंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे प्रदूषण मुक्त अभियान के तहत ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है। इसके तहत पुराने डीजल इंजनों का आधुनिकीकरण कर उन्हें इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जा रहा है।

रक्षा के लिए

- केंद्रीय बजट 2019-20 में इस बार रक्षा क्षेत्र के लिये 3.18 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं, बीते साल के बजट में यह राशि 2.98 लाख रुपये थी।
- रक्षा बजट के लिए आवंटित कुल राशि में से 1,08,248 करोड़ रुपये नए हथियारों, प्लेटफार्मों और सैन्य हार्डवेयर की खरीद के वास्ते पूँजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं।
- वेतन के भुगतान और प्रतिष्ठानों के रखरखाव पर खर्च समेत राजस्व व्यय को 2,10,682 करोड़ रुपये आंका गया है। 2018-19 के बजट में यह 1,88,118 करोड़ रुपये था।
- कुल बजट में पेंशन के भुगतान के लिए अलग से निर्धारित 1,12,079 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं। अगर पेंशन के आवंटन को जोड़ दिया जाता है, तो रक्षा बजट 4.31 लाख करोड़ रुपये पहुँच जाता है, जो वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार के कुल खर्च का 15.47 प्रतिशत है।

कर (टैक्स) प्रावधान

- 5 लाख रुपये तक कि आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- वित्त मंत्री ने 25 प्रतिशत कॉरपोरेट कर के लिए सीमा 250 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर करने की घोषणा की।
- इसका मतलब है कि अब सालना 400 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। पहले सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपए वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत टैक्स देना होता था।
- ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा।
- माध्यम वर्ग को 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है।
- इसके अतिरिक्त 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी।
- यदि कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2 प्रतिशत का TDS लगाया जाएगा। यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे।
- अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. वर्तमान बजट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. इस बजट में चार सौ करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर 25 से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया गया है।
2. इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जी.एस.टी. 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. In the context of present Budget, Consider the following statements-

1. In this buget the corporate tax has been increased from 25 percent to 30 percent for the companies doing trade of Rs. 400 crore yearly.
2. The GST on Electric vehicles has been decreased form 12% to 5%

Which of the above statement is /are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्न: भारत में नई सरकार बनने के साथ ही बजटीय प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया गया। यह बजट वर्तमान सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 'न्यू इंडिया' को पूरा करने में कहाँ तक सहायक होगा? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. Budeget process was performed with the formation of new goverment in India. To what extent, this budget will be helpul in attaining the dream project ' New India' of the present goverment. Discuss (250 Words)

नोट : 5 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।